Volume-3, No. I, Feb-2016, pp. 73-75

ग्रामीण भारत एवं ज्ञान क्रांति

डा. प्रशांत कुमार,
प्रवक्ता, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ उ.प्र. भारत।

सार– केन्द्र सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में ज्ञान क्रांति लाकर देश को साधन संपन्न बनाकर बेरोजगारी, निर्धनता, अशिक्षा, कुपोषण के मकड़जाल में फंसी देश की 25 करोड़ से अधिक जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार की अपेक्षा है। राष्ट्र को कृषि प्रधान समाज से ज्ञानवान समाज में बदलने की प्रक्रिया में मानव अभिकरणों को आपस में जोड़ना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति डा० ए. पी. जे. अब्दुल कलाम की पुस्तक 'इंडिया विजन 2020' में कहा गया है, ''भारत के भावी विकास की गति काफी बड़ी सीमा तक नवीनतम तथा सर्वाधिक उपयोगी जानकारी जनसंख्या के सभी बड़े वर्गों को उपलब्ध कराने की इसकी क्षमता पर निर्भर करेगी।'' मिशन 2007 पांडिचेरी में सन् 1998 में प्रारंभ की गई सूचना ग्राम अनुसंधान परियोजना (आईवीआरपी) के अनुभवों पर आधारित थी। इस मिशन का लक्ष्य था सूचना ग्राम अनुसंधान परियोजना मॉडल को भारत के 60वें स्वतंत्रता दिवस तक 6,00,000 गांवों तक पहुंचा कर तथा ग्रामीण विकास से जुड़े अनेक लोगों को इसका सहभागी बनाकर ग्रामीण विकास को एक नयी दिशा दी जा सके।

मुख्य शब्द– मिशन 2007, ई–प्रशासन, ग्रामीण विकास

ग्लोबल विलेज की इस अवधारणा को ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। ज्ञान क्रांति अर्थात सूचना सम्प्रेषण के वो तमाम साधन ग्रामीण वासियों से सुपरिचित कराने होगें तभी समग्र विकास की कल्पना की जा सकती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण विकास हेतु एक नये दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

यह हमारे देश का सौभाग्य ही कहा जाएगा कि आज देश को ज्ञान क्रांति के माध्यम से विश्व में स्थापित करने की मुहिम चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, संपूर्ण भारत में ज्ञान क्रांति लाकर देश को साधन संपन्न बनाकर बेरोजगारी, निर्धनता, अशिक्षा, कुपोषण के मकड़जाल में फंसी देश की 25 करोड़ से अधिक जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार लाकर उन्हें यह अहसास कराना चाहते हैं कि सरकार उनके दुख, दारिद्रय को दूर करके उन्हें एक बेहतर नागरिक बनाने के लिए कृतसंकल्प है। केंद्र सरकार ज्ञान क्रांति, सूचना–संचार प्रौद्योगिक क्रांति, मेक इन इण्डिया जैसी परियोजनाओं को लागू करके समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से पिछड़ों, दलितों, विकास की छाया से अछूते रहे अल्पसंख्यकों, आदिवासियों आदि का उत्थान करने के लिये प्रतिबद्ध है। विश्व विख्यात तकनीकीविद सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन इसी प्रक्रिया की एक कड़ी था। राजीव गांधी के शासनकाल में टीकाकरण मिशन, पेयजल मिशन, संचार मिशन, पीत क्रांति जैसे अति महत्वाकांक्षी मिशन प्रारंभ कराकर सैम पित्रोदा चर्चा में आए थे। इसे देश में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का आज जो विश्व स्तरीय ढांचा खड़ा हुआ है।

अब देश की एक अरब से अधिक जनसंख्या में मानव विकास के लिये सूचना संचार प्रौद्योगिकी के सकारात्मक प्रयोग हेतु विकासात्मक हस्तक्षेप की पहल की जा रही है। 'वन वर्ल्ड साउथ एशिया' नामक एक गैरसरकारी संगठन ने अपने अन्य अनेक सहयोगियों के साथ मिलकर सन् 1998 से दक्षिण एशिया में अनेक विकास संगठनों के कार्य में सूचना संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया है। इन वर्षों में दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। इसके परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अभिनव प्रयोग किए गए हैं तथा भारत के सूचना संचार प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने वैश्विक स्तर पर अपने ज्ञान का लोहा मनवाया है। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तीव्र संवृद्धि एवं विकास का लाभ अपने ही देश के एक बड़े वर्ग–हाशिए पर रहे पिछड़ों तथा निर्धनों–को उस सीमा तक नहीं मिल सका है जिसकी कि अपेक्षा की गयी थी।

मिशन 2007: कृषकों पर राष्ट्रीय आयोग ने सारे देश में आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले ग्रामीण सूचना केंद्रों की स्थापना किए जाने की सिफारिश की है। इसी सिफारिश को कार्यरूप देने एवं भारत के समग्र एवं त्वरित विकास हेतु सूचना संचार प्रौद्योगिकी की संभावना का उपयोग करने के लिए सन् 2007 में 'मिशन 2007' के नाम से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ किया गया, क्योंकि सूचना संचार प्रौद्योगिकी में ज्ञान प्रवाहित करके ग्रामीण विकास प्रक्रिया में जान फूंक देने की विशाल संभावना है। राष्ट्र को कृषि प्रधान समाज से ज्ञानवान समाज में बदलने की प्रक्रिया में मानव अभिकरणों को आपस में जोड़ना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति डा० ए. पी. जे. अब्दुल कलाम की पुस्तक 'इंडिया विजन 2020' में कहा गया है, ''भारत

के भावी विकास की गति काफी बड़ी सीमा तक नवीनतम तथा सर्वाधिक उपयोगी जानकारी जनसंख्या के सभी बड़े वर्गों को उपलब्ध कराने की इसकी क्षमता पर निर्भर करेगी।''

मिशन 2007 पांडिचेरी में सन् 1998 में प्रारंभ की गई सूचना ग्राम अनुसंधान परियोजना (आईवीआरपी) के अनुभवों पर आधारित है। इस मिशन का लक्ष्य सूचना ग्राम अनुसंधान परियोजना मॉडल को भारत के 60वें स्वतंत्रता दिवस तक 6,00,000 गांवों तक पहुंचा कर तथा ग्रामीण विकास से जुड़े अनेक लोगों को इसका सहभागी बनाकर ग्रामीण विकास को एक नयी दिशा देने की थी। यह मिशन नागरिक–सामाजिक संगठनों सहित देश के 80 से अधिक संगठनों के एक राष्ट्रव्यापी गठबंधन द्वारा प्रारंभ किया गया था। विश्व के अनेक देशों में सूचना संचार प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान कराने में 'इंफोक्योस्क' अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हुए हैं। इन्हीं इंफोक्योस्कों के प्रयोग के द्वारा भारत के प्रत्येक गांव तक सूचना संचार प्रौद्योगिकी को पहुचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मिशन का अंतिम उद्देश्य भारत को एक ज्ञानवान समाज के रूप में स्थापित करना है। मिशन 2007 को सफलतापूर्वक प्रारंभ करने के लिये 2004 में राष्ट्रीय नीति निर्धारकों की एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे :

- पहले चरण में 25,000 गांवों को सूचना संचार, प्रौद्योगिकी संपर्क से जोड़ा जाये।
- ग्रामीण सेवा प्रदान करने वालों के लिये उपयोगी दशाओं एवं प्रोत्साहनों को चिह्नित करके उनके सृजन की व्यवस्था करना।
- उद्देश्यों की सफलता इस बात में निहित है कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी के सभी सॉफ्टवेयर स्थानीय उद्यमियों के लिये स्थानीय भाषाओं एवं बोलियों में विकसित किए जाये।
- 10 लाख ग्रामीण बुद्धिजीवियों, विशेष रूप से महिलाओं को प्रशिक्षित करने में गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाए।
- स्थानीय विकेंद्रीकृत नियोजन हेतु स्थानीय आंकड़ों के उपयोगकर्ताओं तथा स्थानीय आंकड़ों के संपार्विकों के रूप में स्थानीय समुदायों का सशक्तीकरण एवं चिह्नित करना।
- राष्ट्रीय स्तर के एक सूचना संचार प्रौद्योगिकी आयोग की स्थापना हेतु गठबंधन को विधिक मान्यता प्रदान करना।
- लक्षित समूहों एवं लाभार्थियों की आवश्यकताओं एवं अवगमों का मूल्यांकन करना। यह भारत में ज्ञान क्रांति की सफलता की एक आवश्यक शर्त प्रौद्योगिकी के मानवीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा।

यदि हम देश में ज्ञान क्रांति लाने के लिये सूचना संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का विस्तार करने (विशेष तौर पर इंफोक्योस्कों के उपयोग) के लिये सहमत हो जाते हैं तो मशीनों की सहायता हेतु संसाधनों (मानव शक्ति एवं वित्तीय दोनों ही प्रकार के) से जुड़े मुद्दों को हल करना भी महत्वपूर्ण होगा। वर्तमान केन्द्र सरकार भी इस दिशा में बहुत गम्भीर प्रयास कर रही है। वर्तमान सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 2017 तक देश के प्रत्येक गॉव को सूचना तन्त्र इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने आगे कहा कि इसके पश्चात प्रत्येक घर को सूचना क्रांति से जोड़ा जायेगा।

ज्ञान क्रांति के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जहां नयी सूचना का सृजन महत्वपूर्ण है, वहीं विद्यमान ज्ञान एवं सफलताओं–असफलताओं से युक्त नये प्रयोगों का अभिलेखन एवं संरक्षण भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

ई–प्रशासन : नागरिकों के द्वार तक सरकारी सेवाओं, विशेष रूप से सूचनाएं एवं सरकारी गतिविधियों की जानकारी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार ने 23,000 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाली ई–प्रशासन की एक अति महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत 26 मिशन मोड परियोजनाओं तथा 8 सहायक संघटकों का कार्यान्वयन केंद्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर चलाया जाएगा। परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक विशेष एकांश की स्थापना की जा रही है तथा कार्यान्वयन की देखरेख, नीतिगत निर्णय लेने और रणनीतिक दिशानिर्देश देने के लिये कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति भी गठित की गई है। ई–प्रशासन के अंतर्गत राज्य स्तर पर निम्नलिखित सेवाएं सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों को मुहैया कराई जाएगी। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने इस दिशा में कुछ प्रगति भी की है। प्रायोगिक तौर पर ई–प्रशासन को निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रारंभ किया जा रहा है :

• भू–अभिलेख • वाणिज्यिक कर • रोजगार केंद्र
• कोषागार • भू–पंजीयन • पुलिस प्रशासन • शिक्षा

ई–प्रशासन पूरी तरह से लागू हो जाने पर कोई भी किसान भूमि पर अपने अधिकार, स्वामित्व संबंधी प्रमाणपत्र, राजस्व भुगतान की रसीद, खसरा–खतौनी की नकल, स्वामित्व हस्तांतरण संबंधी निर्णयों की प्रगति प्राप्त कर सकेगा। रोजगार केंद्रों पर रिक्तियों की सूचना कप्यूटर पर उपलब्ध होगी।

केंद्र स्तर पर बीमा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राष्ट्रीय परिचयपत्र, पासपोर्ट, वीजा, पेंशन, ई–पोस्ट, बैंकिंग तथा आयकर और निगम कर जैसी सेवाओं से

संबंधित जानकारी प्राप्त की जा रही है। पासपोर्ट हेतु आवेदनपत्र ऑनलाइन भरे जाने की व्यवस्था की जा चुकी है। यह सब इसी का परिणाम है।

राष्ट्रीय ई–प्रशासन परियोजना का आकार कितना बड़ा है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इसके कार्यान्वयन में 500 से अधिक कार्यान्वयन अभिकरण, दो लाख से अधिक स्थल तथा 70 हजार से अधिक मानव वर्ष प्रयास शामिल है। परियोजना की अनुमानित लागत 23,000 करोड़ रूपये है जिसमें 10,000 करोड़ रूपये आधारित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन पर खर्च होंगे तथा मिशन मोड परियोजनाओं पर अगले पांच वर्षों में 13,000 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे।

वर्तमान में केंद्र एवं राज्य सरकारें प्रतिवर्ष लगभग 10,000 करोड़ रूपये ई–प्रशासन से जुड़ी परियोजनाओं पर खर्च कर रही है। ये सेवाएं अलग–अलग दिशाओं में कुछ विशिष्ट उद्देश्यों से ही प्रारंभ की गई है। ई–प्रशासन की राष्ट्रव्यापी परियोजना के अंतर्गत इन सभी को समन्वित रूप से एक मानक प्लेटफार्म पर लाया जाना है। प्रत्येक विभाग को अपना स्वयं का सॉफ्टवेयर चुनने की छूट दी गई है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के साथ मिलकर ऐसे मानक तैयार करेगा जो सेवाओं को कारगर ढंग से प्रदान करने में सहायक हो तथा सामान्य–सी जानकारी रखने वाला नागरिक भी सरकारी सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम हो सके।

ग्रामीण विकास के लिए चाहिए नया दृष्टिकोण : देश की राष्ट्रीय आय में एक बड़ा अंशदान ग्रामीण वासियों द्वारा किये जाने के बाद भी गांव विकास की दौड़ में पीछे छूट गये हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना अपरिहार्य हो गया है। अनुभव बताते हैं कि अत्यन्त विकसित कहे जाने वाले राष्ट्र भी विकास के इस पायदान पर तभी पहुंच सके हैं जब उनके गांवों का विकास भी तीव्र गति से हुआ है। ऐसे में ग्रामीण विकास हेतु एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

विकास का प्रमुख लक्ष्य एक ऐसी समतावादी समाज–व्यवस्था को स्थापित करना है, जहां पर सभी व्यक्ति समान हों, सभी को अवसरों की समानता हो तथा विभिन्न क्षेत्रों समाज वर्गों एवं लोगों में विषमता न हो, परन्तु स्वतन्त्रता के 69 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक असमानता देखने को मिलती है। एक ओर जहां शहरी क्षेत्र तेजी से विकास की ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र विभिन्न अभावों के साथ विकास के समुचित लाभ से वंचित हैं।

विकास से सम्बन्धित उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में ग्रामीण लोगों की उच्चस्तरीय सेवाओं तक पहुंच तुलनात्मक दृष्टि से पिछड़ी अवस्था में है। आर्थिक उदारीकरण एवं संरचनात्मक परिवर्तन के दौर में बड़े नगर विकास की धुरी बनकर उभरे हैं। नवोन्मुखी रोजगार एवं सुविधाएं इन्हीं शहरों तक सिमट कर रह गई हैं। दूसरे क्षेत्रों में परिवर्तन की गति गांवों की तुलना में कहीं अधिक है। इसके परिणामस्वरूप गांव एवं शहर के बीच असमानता बढ़ी है।

सारांश

विश्व में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनकी 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती हो और ग्रामीण क्षेत्र ही उस देश की सम्पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का आधार हों। भारत में एक ओर जनसंख्या का अधिकांश भाग गांवों में निवास करता है तो दूसरी ओर 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि के द्वारा आजीविका उपार्जित करती है। देश की राष्ट्रीय आय में एक बड़ा अंशदान ग्रामीण समुदाय द्वारा किये जाने के बाद भी गांव विकास की दौड़ में पीछे छूट गये हैं। ऐसे में तीव्र गति से विकास करने और विकसित देशों की श्रेणी में स्वयं को खड़ा करने की प्रक्रिया में ग्रामीण समाज के विकास को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना अपरिहार्य हो गया है क्योंकि अद्यतन परिवर्तनशील प्रणाली में ग्रामीण विकास देश की भावी आर्थिक बेहतरी एवं समग्र विकास की कुंजी है।

ग्लोबल विलेज की इस अवधारणा को ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। ज्ञान क्रांति अर्थात सूचना सम्प्रेषण के वो तमाम साधन ग्रामीणवासियों से सुपरिचित कराने होगें तभी समग्र विकास की कल्पना की जा सकती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण विकास हेतु एक नये दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आशा और अपेक्षा है कि वर्तमान सरकार इस ओर कुछ नये प्रयासों के साथ इस दिशा में कार्य करेगी।

सन्दर्भ सूची

1. कुमार, राजीव, जनवरी 2009, ग्रामीण विकास के लिए चाहिए नया दृष्टिकोण, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. Mathur, K.B., 1994, Communication Rural Development & Social change, New Delhi, Allied Publishers.
3- Agarwal, Binode, 1986, Communication Research for Development, New Delhi, Concept Publishing.
4- Raghavan, G.N.S., 1992, Development and Communication in India, New Delhi, Gyan Publishing House.
5- Sinha, Arbind K, 1985, Mass Media and Rural Development, Delhi, Concept Publishing.
6. http://rd.up.nic.in/